भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 713

मंगलवार, 22 नवम्बर, 2016/1 अग्रहायण, 1938 (शक)

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु सरकारी समिति

713. श्री नीरज शेखर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री सहित मंत्रियों के समूह ने विभिन्न श्रमिक संघों/जेसीएम के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया था कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन तथा फिटमेंट फार्मूले के संशोधन की मांग पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसे अपनी रिपोर्ट को चार माह के भीतर अंतिम रूप प्रदान किए जाने का अधिदेश दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो समिति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) चार माह बीत जाने के बावजूद उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भत्तों संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय परिषद् (स्टाफ पक्ष), संयुक्त परामर्शी तंत्र के प्रतिनिधियों को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में, वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने इस संबंध में प्रतिनिधियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बैठकें की हैं।

(घ) से (च): भत्तों से संबंधित समिति विभिन्न हितधारकों के साथ उनकी मांगों के संबंध में विचार-विमर्श कर रही है और अब तक राष्ट्रीय परिषद् (स्टाफ पक्ष), संयुक्त परामर्शी तंत्र, कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डाक विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर चुकी है। अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले यह समिति कुछ अन्य प्रमुख मंत्रालयों/विभागों तथा हितधारकों के प्रतिनिधियों जिनके साथ अभी विचार-विमर्श किया जाना है, के साथ भी बातचीत कर सकती है।

*****